इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश के चीनी का SAP बढ़ाने की आशंका

[जयश्री भोसले | पुणे]

उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव सरकार गन्ने के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (राज्य परामर्श मूल्य या एसएपी) में बढ़ोतरी करेगी। अगर ऐसा होता है तो यह तीन सालों में होने वाला पहला रिवीजन होगा। राज्य परामर्श शुल्क या एसएपी को पिछली बार 2012-13 में रिवाइज किया गया था। यहआमतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से तय किए जाने वाले मूल्य से अधिक होते हैं।

इंडस्ट्री से जुड़े एक एग्जिक्यूटिव ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'राज्य की शुगर रिकवरी में करीब 1 फीसदी की बढ़ोतरी, चीनी की कीमतों में सुधार और चुनावी साल का मतलब है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से गन्ने के दाम में बढ़ोतरी करेगी।' वहीं, केंद्र सरकार ग्रामीण वोटरों के सामने अपनी किसान समर्थक नीतियों को पेश करने की कोशिश कर रही है। वह चीनी की खुदरा कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी रोकने की भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस साल जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन 6.07 फीसदी के साथ 23 महीने में सबसे ज्यादा हो गई थी। एग्जिक्यूटिव्स का कहना है कि सरकार को सभी चिंताओं के साथ सामंजस्य बनाना होगा।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तरुण साहनी का कहना है, '2016-17 में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में प्रॉडक्शन घटने के आसार हैं। ज्यादा पैदावार वाली गन्ने की नई वैरायटी और रिकवरी के साथ-साथ हर जगह होने वाली बारिश से उत्तर प्रदेश को टॉप शुगर प्रोड्यूसर बनने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'इस समय, मुझे उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां सभी चिंताओं को दूर करेंगी।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में शाहजहांपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया था। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक क्षेत्र का एक हिस्सा है। पीएम मोदी ने इस रैली में कहा था कि उनकी सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन दिए हैं और एथनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। साथ ही, एथनॉल ब्लेंडिंग को 5 से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया है ताकि चीनी मिलें गन्ने की बकाया रकम किसानों को चुका सकें। हालांकि, एनालिस्टों का कहना है कि केंद्र सरकार के लिए यह मुश्किल काम होगा, क्योंकि यह चीनी की खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार एक्सपोर्ट को हतोत्साहित करने, ट्रेडर्स पर एक स्टॉक लिमिट लगाने जैसे कदमों के जरिए चीनी की रिटेल कीमतों को 40 रुपये प्रति किलो पर रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इंडस्ट्री का कहना है कि इन कदमों से उन्हें किसानों का बकांया चुकाने में मदद नहीं मिलेगी। हालांकि, एक साल पहले के मुकाबले गन्ने का बकाया एरियर भुगतान काफी घटा है, देश भर में अब भी शुगर मिलों में किसानों को करीब 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।